साप्ताहिक

जागत गांव हमार

पंचायत की विकास गाथा, सरकार तक

RNI-MPHIN/2019/78930

चौपाल से भोपाल तक

मुरैना, सोमवार 09-15 जनवरी , 2023 वर्ष-5, अंक-7

मुरैना, भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, रीवा, शिवपुरी से एक साथ प्रकाशित

पृष्ठ :-8, मूल्य :- 2 रुपए

कृषि क्षेत्र में पानी बचाने के लिए जनता को जागरूक करने की जरूरत

देश में जन-जन का आंदोलन बने जल आंदोलन

जागत गांव हमार, भोपाल।

सेंस ऑफ ऑनरशिप सफलता की कुंजी है। जब किसी अभियान से जनता जुड़ी रहती है, तो उसे कार्य की गंभीरता भी पता चलती है। इससे जनता में किसी योजना या अभियान के प्रति सेंस ऑफ ऑनरशिप आती है। यही सफलता की कुंजी है। यह कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। वह देश के हृदय प्रदेश की राजधानी में वाटर विजन 2047 के तारतम्य में आयोजित राज्य मंत्रियों के पहले सम्मेलन को वर्चुअली संबोधित कर रहे थे।

राजधानी के कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन हाल में आयोजित उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने पानी बचाने पर जोर दिया। साथ ही उद्योग और कृषि दोनों क्षेत्र में पानी बचाने के लिए जनता को जागरूक करने की जरूरत बताई। पानी को ध्यान में रखकर अगले 5 साल के लिए ग्राम पंचायतों को योजना बनाने की आवश्यकता बताते हुए कहा कि यह अभियान अगले 25 वर्षों का महती अभियान है। हमारी सभी सरकारें एक व्यवस्था के तहत इसमें काम करे। इसका साथ ही उनका कहना था कि पॉलिसी लेवल पर पानी से जुड़ी परेशानियों के समाधान के लिए सरकारी नीतियां और ब्यूरोक्रेटिक प्रक्रियाओं से बाहर आना होगा। हमें समस्या को पहचानने और उसके समाधान को खोजने के लिए तकनीकि, उद्योग और खासकर स्टार्टअप्स को साथ जोड़ना होगा। उनका कहना था कि जियो-सेन्सिंग और जियो मैपिंग जैसी तकनीकों से हमें इस दिशा में काफी मदद मिल सकती है।

सफलता की कुंजी है सेंस ऑफ ऑनरशिप, वाटर विजन 2047 को लेकर राज्य मंत्रियों के सम्मेलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा

ड्रॉप-मोर क्रॉप अभियान को प्रोत्साहित करना आवश्यक

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने कहा कि फसल विविधीकरण और प्राकृतिक खेती, जल-संरक्षण पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। देश में ड्रॉप-मोर क्रॉप अभियान को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। उन्होंने अटल भू-जल संरक्षण योजना में भू-जल पुर्नभरण के लिए माइक्रो स्तर पर गतिविधियाँ संचालित करने की आवश्यकता भी बतायी।

ये रहे उपस्थित

कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, केंद्रीय जलशक्ति राज्यमंत्री प्रहलाद पटेल इस दौरान प्रमुख रूप से मौजूद थे। इनके साथ ही मप्र के जल संसाधन मंत्री तुलसी राम सिलावट, उप्र के जल संसाधन मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, उत्तराखंड के सिंचाई मंत्री सतपाल महराज सहित कई राज्यों के जल संसाधन, पीएचई मंत्री कार्यक्रम में मौजूद थे।

जलनीति बना रहा है मपः शिवराज

कार्यक्रम को मुख्यअतिथि के रूप में संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पानी के महत्व व उसकी जरूरत को रेखांकित करते हुए कहा, मप्र जलनीति बना रहा है। इसके तहत वह पानी बचाने और उसे बढ़ाने पर जोर दे रहा है। इस सम्मेलन के माध्यम से जो सुझाव आएंगे उसे भी इसमें शामिल किया जाएगा। उनका कहना था कि जल संरक्षण अभियान में जनता को जोड़ने के लिये मप्र सरकार ने जलाभिषेक, जलसंसद और जल यात्रा जैसे प्रकल्प शुरू किये हैं। इसके पहले भोपाल को जलसंरक्षण के मामले में देश का अद्भुत उदाहरण बताते हुए कहा कि यहां का बड़ा तालाब एक तिहाई जल आपूर्ति कर रहा है। साथ बीते सालों में सरकार द्वारा किये गये प्रयासों को सामने रखते हुए कहा कि पहले यहां मात्र साढ़े सात लाख हेक्टेयर क्षेत्र में खेती होती थी अब यह बढ़कर 45 लाख हेक्टेयर हो गई है। भविष्य में इसे 65 लाख तक ले जाने का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि मप्र में जल-संरक्षण और उसके मितव्ययी उपयोग के लिए संवेदनशीलता के साथ गतिविधियां संचालित की जा रही हैं। प्रदेश में वर्ष 2003-04 तक सिंचाई क्षमता 7 लाख 50 हजार हेक्टेयर थी, जो अब बढ़ कर 43 लाख हेक्टेयर हो गई है।

संसाधनों को चिह्नित करने के बाद प्रबंधन की जरूरतः शेखावत

केंद्रीय जलशक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अपने उद्बोधन में कहा कि आज पानी पर काम करने के लिए पहली जरूरत ये है कि हम अपने संसाधनों को पहचानें। जब हम इसे चिह्नित कर लेंगे, तब हम जलप्रबंधन की दिशा में काम कर सकेंगे। यह इसलिये भी जरूरी है क्योंकि भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। पूरा विश्व इस बात को स्वीकार करता है कि 2027 तक हम जापान और जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की क्षमता हैं। पर इसके साथ पानी और बिजली की खपत भी बढ़ेगी। इसे देखते हुए हमें समग्र रूप से प्रबंधन की जरूरत है।

सहरिया संस्कृति को भी चाहिए संरक्षण

एक रोज सुबह 4 बजे बांधवगढ़ के एक रिसोर्ट में पहुंचा। कमरा खुला और बत्ती जलाते ही कुछ लुभावनी पेंटिंग दिखाई दीं। इन पेंटिंग को गोंड आर्ट के नाम से दुनिया भर में जाना जाता है। कमरे में लगी सभी पेंटिंग ऑरीजनल थीं, जो कलाकारों से सीधे खरीदी गई थीं। जिज्ञासा वश पेंटर का नाम जानने चित्रों को नजदीक से देखा, तो टेढ़ी बाई लिखा था, इसी तरह के जनजातीय नाम दूसरी पेंटिंग पर थे। इसे देखकर अचानक चंबल संभाग के सहरिया आदिवासियों और उनके स्वांग नृत्य का खयाल आया, जिसे आवश्यक संरक्षण नहीं मिल पा रहा है। दरअसल बांधवगढ़ के आसपास रहने वाले और ये पेंटिंग बनाने वाले लोग आदिवासी हैं, जो गोंड जनजाति के हैं। हालांकि 1980 के बाद से लगातार चमक रही इस कला को दूसरे चित्रकार भी सीख रहे हैं या काम कर रहे हैं। इस कला ने आदिवासियों की इस गोंड जनजाति को एक तरह से ब्रांड नेम में बदल दिया है। गोंड चित्रकला पूरी तरह से प्रकृति और जनजाति की परंपराओं पर आधारित होती है। इसमें रंगों का संयोजन ही मुख्य है। मसलन एक हाथी के या मोर के खाली चित्र को किस तरह से कल्पनाओं के रंग से भर दिया गया है, यह दिखाई दे जाना ही कलाकार की कला है। गोंड चित्रकला इस जनजाति के सुख, दुख और उत्सव को दर्शाती है। घर में विवाह होने पर अलग चित्र बनाए जाते हैं। मृत्यु के अवसर पर अलग। इसी तरह फसल कटने पर यहाँ तक कि घर में नए मेहमान के आने की तैयारियों में अलग तरह के चित्र गोंड जनजाति के लोग अपने घरों पर तैयार करते हैं। मध्यप्रदेश के अलावा आर्ट शोरूम में इन चित्रों के अलग गलियारे हैं, विलायत के संग्रहालयों में भी यह गोंड आर्ट अच्छी जगह बना चुके हैं। ऐसे ही प्रोत्साहन की जरूरत चंबल के सहरिया आदिवासियों को भी है। मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहरिया आदिवासी बाहुल्य इलाकों में उनके स्वास्थ्य, शिक्षा आदि के लिए कई योजनाएं शुरू की हैं। लेकिन अब आवश्यकता है कि सहरिया आदिवासियों की संस्कृति को भी संरक्षित किया जाए। सहरिया संस्कृति में सबसे प्रसिद्ध है स्वांग नृत्य इस नृत्य को नगाड़े और मिट्टी के मटको की धुन पर सहरिया आदिवासी विशेष अवसरों पर समूह में प्रस्तुत करते हैं। इस नृत्य के लिए सहरिया कलाकार अपने शरीर पर प्राकृतिक रंग और फूल, पत्तों से सजावट करते हैं। मुरैना में स्थित पंडित राम प्रसाद बिस्मिल संग्रहालय में स्वांग नृत्य के बारे में न के बराबर ही जानकारी और प्रदर्श सामग्री उपलब्ध है। ऐसे में अगर सहरिया जनजाति के सुप्रसिद्ध स्वांग लोकनृत्य से जुड़ी जानकारियां इस संग्रहालय में प्रदर्शित की जाएँ तो लोगों को इस संस्कृति के बारे में बहुत कुछ मालूम हो सकता है ।

शिवप्रताप सिंह जादौन
संपादक

मुख्यमंत्री ने टीकमगढ़ से मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना की शुरूआत

प्रदेश में नई सामाजिक क्रांति की शुरूआत प्रदेश में हर गरीब का होगा पक्का मकान

जागत गांव हमार, भोपाल।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रदेश में टीकमगढ़ से आज नई सामाजिक क्रांति की शुरूआत हुई है। प्रदेश में अब कोई भी व्यक्ति घास-फूस के अथवा कच्चे मकान में नहीं रहेगा। सरकार सभी गरीब आवासहीन व्यक्तियों को आवासीय भूमि के पट्टे दिलवायेगी। प्रधानमंत्री आवास योजना और मुख्यमंत्री जन-आवास योजना में इन पट्टों पर पक्के मकान बनवाये जायेंगे। ये केवल पट्टे नहीं, बल्कि गरीबों का सम्मान, उनकी इज्जत है। अब उनसे कोई यह नहीं कह सकेगा कि इस जगह से हटो।

10 हजार 918 हितग्राहियों को भू-खण्ड वितरित किए गए

मुख्यमंत्री चयनित हितग्राहियों को आवंटित भू-खण्डों पर पहुंचे और वहीं उन्हें स्वीकृति-पत्र वितरित किये। उन्होंने हितग्राहियों से बातचीत की और उनके साथ जमीन पर बैठ कर भोजन भी किया। मुख्यमंत्री ने वहां अधिकारियों को निर्देश दिये कि आवंटित भू-खण्डों के आसपास सभी बुनियादी सुविधाएं सड़क, बिजली, पानी, सीवेज लाइन आदि उपलब्ध करवायी जाये। कार्यक्रम में जिले के कुल 10 हजार 918 हितग्राहियों को 129 करोड़ 37 लाख रूपये के भू-खण्ड वितरित किये गये। साथ ही उन्होंने 255 करोड़ के विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया।

6 अप्रैल से फिर लगेगा शिविर

समारोह में मुख्यमंत्री ने कहा कि यहां कोई राजा नहीं है-मुख्यमंत्री, मंत्री, सांसद, विधायक, कमिश्नर, कलेक्टर सब जनता के सेवक हैं। हमारा काम है कि जनता को अपने कार्यों और शासकीय योजनाओं के लाभ के लिये इधर-उधर भटकना न पड़े। हम सब जनता के पास जाकर सेवाएं दें। प्रदेश में मुख्यमंत्री जन-सेवा अभियान में हर गांव, हर वार्ड में शिविर लगा कर जनता के कार्य किये गये। उन्होंने टीकमगढ़ जिले में प्राप्त एक लाख 52 हजार आवेदनों में से एक लाख 44 हजार आवेदनों के निराकरण के लिये जिला प्रशासन को बधाई दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी 6 अप्रैल से फिर अभियान के शिविर लगाए जाएंगे।

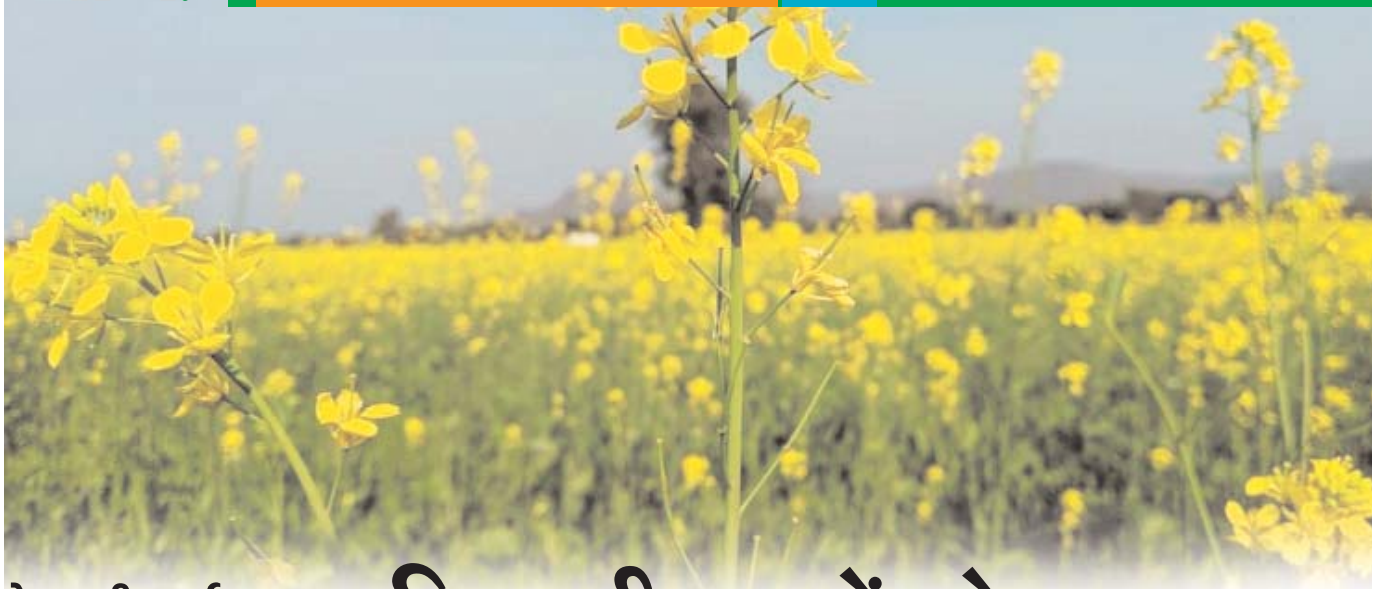

देश की अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका अदा करती हैं

तिलहनी फसलें, जो कम लागत में दे सकतीं हैं ज्यादा मुनाफा

जागत गांव हमार, भोपाल।

पिछले कुछ दशकों से केंद्र एवं राज्य सरकारें तिलहनी फसलों के रकबे में बढ़ोतरी के लिए कई विभिन्न प्रकार की योजनाएं संचालित कर रही हैं। क्योंकि तिलहनी फसलें देश की अर्थव्यवस्था में मुख्य भूमिका अदा करती हैं। देश के कई हिस्सों में खरीफ, रबी और जायद तीनों ही कृषि मौसम में अलग-अलग तिलहन फसलों की खेती होती है। जिनमें अलसी, कपास, तिल, सूरजमुखी, सरसों, सोयाबीन, मूंगफली, अरंडी, बदाम, पाम आदि खाद्य तिलहनी फसलों की खेती परंपरागत रूप से की जाती है। उत्पादन और क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से देखा जाये तो मूंगफली, सोयाबीन और सरसों देश की प्रमुख तिलहन फसलें हैं।

असली की खेती- कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन में असली की खेती प्रमुख तौर पर की जाती है। असली दो रंग की होती है, भूरा और पीला। इन दोनों किस्मों की खेती के लिए अच्छी उपजाऊ और नमीदार मिट्टी उपयुक्त रहती है, जिससे असली का अच्छा उत्पादन मिले और ज्यादा मात्रा में तेल निकला आए। आमतौर पर असली के तेल का इस्तेमाल अलसी पेंट, वार्निश, छपाई और अन्य उत्पादों में किया जाता है। वैसे तो असली से भी फूड ऑइल निकलता है, लेकिन भारत में लोग इसके तेल को कम ही खाना पंसद करते हैं।

कपास की खेती| कपास के बीजों को बिनैला कहते हैं। इससे निकलने वाला तेल खाना बनाने में इस्तेमाल होता है। कई देशों में सलाद की ड्रेसिंग के लिए भी इस तेल का इस्तेमाल होता है। बिनौला भी अपने आप में एक बड़ी नकदी फसल है, जिसका उत्पादन पूरी दुनिया में होता है। कई देशों में भारत से ही बिनौला ऑइल या बिनौला कैटल फीड निर्यात होती है।

तिल की खेती| तिल के बीज बेहद छोटे होते हैं। इसके तेल का इस्तेमाल भी पूजा-पाठ से लेकर खाना बनाने, त्वचा और बालों की देखभाल के लिए किया जाता है। किसी भी बीज के मुकाबले तिल में ज्यादा तेल मौजूद होता है। अच्छी क्वालिटी के तिल के लिए उन्नत बीज, उपजाऊ और नमीदार मिट्टी का होना जरूरी है। इसकी अच्छी पैदावार किसानों के लिए मददगार साबित हो सकती है।

सूरजमुखी की खेती| सूखा और गर्मी में भी सूरजमुखी के पौधे जस के तस खड़े रहते हैं। ये गर्मी में ज्यादा अच्छी तरह खिलते हैं। सूरजमुखी के फूल से ही बीज मिलते हैं, जिनसे तेल निकाला जाता है। सूरजमुखी के बीजों में 35प्रतिशत नमी होती है। उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में सूरजमुखी की खेती की जाती है।

सरसों की खेती| देश के लगभग हर घर में सरसों का तेल मिल ही जाता है। इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत में सरसों की खपत कितने बड़े पैमाने पर है, लेकिन इसकी खेती सिर्फ रबी सीजन में की जाती है भारत के अलावा संयुक्त राज्य अमेरिका, कनाडा, नेपाल, हंगरी में भी सरसों की खेती बड़े लेवल पर होती है। इस साल भारत में सरसों के न्यूनतम समथर्जन मूल्य बढ़ा दिए गए हैं। सरसों के बाजार भाव भी काफी ज्यादा हैं। सरसों की कीमतों ने ही इस साल किसानों को ये फसल लगाने के लिए काफी प्रेरित किया है।

सोयबीन की खेती| पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाले तेल में सोयाबीन के तेल का नाम भी शामिल है। आज ज्यादातर फूड ऑइल सोयाबीन से ही बनते हैं। दुनिया में सोयाबीन की अच्छी-खासी डिमांड है।

मूंगफली की खेती

मूंगफली को कच्चा बदाम भी कहते हैं। इसके तेल का इस्तेमाल फूड ऑइल के तौर पर किया जाता है। ये तेल भी सेहत के लिए काफी फायदेमंद रहता है। लोग सर्दियों में मूंगफली के तेल का खूब इस्तेमाल करते हैं। बाजार में मूंगफली का तेल 500 से 700 रुपये लीटर तक के भाव पर बिकता है।

अरंडी की खेती

भारत में अरंडी की खेती भी बड़े पैमाने पर की जाती है। इसके बीजों से तेल को निष्कासित करके बालों की देखभाल, त्वचा की देखभाल और तमाम ब्यूटी प्रॉडक्ट्स में इस्तेमाल किया जाता है। बाजार में अरंडी के तेल की अच्छी-खासी डिमांड होती है।

बदाम की खेती

वैसे तो बदाम एक मेवा है, लेकिन इससे तेल भी निकाला जाता है। बादाम के तेल में कई औषधीय गुण होते हैं। यही वजह है कि बाजार में बादाम के तेल की अच्छी-खासी डिमांड होती है। लोग बादाम के तेल को खाने से लेकर बॉडी पर लगाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। कई कॉस्मेटिक उत्पादों से लेकर फूड प्रॉडक्ट्स में भी बादाम के तेल का इस्तेमाल हो रहा है। बाजार में बादाम का तेल 1,500 रुपये प्रति लीटर तक के भाव पर बिकता है।

पाम की खेती

पाम तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए मिशन पाम ऑइल भी चलाया जा रहा है, जिसके तहत पाम की खेती के लिए सरकार सब्सिडी भी देती है। इस तेल का इस्तेमाल मार्जरीन, शॉर्टिंग, खाना पकाने के तेल, कन्फेक्शनरी वसा में इस्तेमाल किया जाता है। खाद्य उत्पादों के अलावा भी पाम ऑइल के कई काम होते हैं।

नाफेड का मिलेट आउटलेट, एक छत के नीचे मिल जाएंगे सारे मोटे अनाज

जागत गांव हमार, भोपाल/नई दिल्ली।

भारत के प्रस्ताव पर 72 देशों के समर्थन के बाद संयुक्त राष्ट्र संघ ने साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित कर दिया है। पूरी दुनिया में भारत ही मोटे अनाजों का सबसे बड़ा उत्पादक है। यही वजह है कि पूरी दुनिया को मिलेट की वैल्यू समझाने की जिम्मेदारी भी भारत पर ही है। इस कड़ी में भारत सरकार ने काम करना चालू कर दिया है। मोटे अनाज को बढ़ावा देने की भारत की तैयारियां जोरों पर हैं। मिलेट्स के बारे में जागरुकता बढ़ाने के लिए नाफेड ने पहल की है और नीति भवन में पहले मोटे अनाजों का आउटलेट लॉन्च किया है। एक ऐसा आउटलेट, जहां एक ही छत के नीचे सारे मोटे अनाज मिल जाएंगे। इस मिलेट आउटलेट को नीति भवन के सीईओ परम अय्यर और वाइस चेयर मैन सुमन के. बेरी ने लॉन्च किया है। इस पहल से मिलिट्स के प्रचार-प्रसार को बढ़ाने में मदद मिलेगी।

क्यों खास हैं मोटे अनाज

- इंसान की बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स बेहद जरूरी है। ये हमें गेहूं-चावल से मिल पाते, लेकिन ज्वार, बाजरा, रागी, कुटकी, कोदो, कंगनी, चेना, कोदरा, ब्लूम कॉर्नज, सांवा, हरी कंगनी, कुट्टू और राजगिरा इन सभी मोटे अनाजों में प्रोटीन, वसा, लौह, रेशा, कैल्शियम और जिंक की भी भरपूर मात्रा होती है।
- इसके नियमित सेवन से शरीर की इम्यूनिटी मजबूत बनती है और हृदय रोग, कैंसर,डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, गठिया रोग,सूजन और तमाम घातक बीमारियों का खतरा कम होता है। किसानों के लिए मोटे अनाजों की खेती बेहद फायदेमंद बताई गई है।
- ये कम लागत में ही पककर तैयार हो जाते हैं। जलवायु की अनिश्चितताओं के बीच सिर्फ मिट्टी, खाद, पानी में मोटे अनाजों को उगाया जा सकता है। इस फसल में कीट-रोग लगाने की संभावना कम ही रहती है, इसलिए उर्वरक-कीटनाशकों का खर्चा भी बच जाता है।
- जलवायु परिवर्तन के दौर में जहां खाद्यान्न उत्पादन कम होने से खाद्य आपूर्ति की समस्या गहराती जा रही है। ऐसे में मोटे अनाजों से ना सिर्फ देश-दुनिया की खाद्य आपूर्ति आसानी से सुनिश्चित हो जाएगी, कुपोषण की समस्या भी दूर होगी

क्यों मनाएं अंतराष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष

साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष के तौर पर मनाया जा रहा है, जो भारतीयों के लिए गर्व की बात है, क्योंकि यह भारत का ही प्रस्ताव था, जिसे 72 देशों ने समर्थन दिया और संयुक्त राष्ट्र संघ महासभा ने 5 मार्च 2021 भी साल 2023 को अंतर्राष्ट्रीय पोषक अनाज वर्ष घोषित कर दिया। यह भारतीय किसानों की मेहनत का ही नतीजा है कि आज भारत मिलेट्स का बड़ा उत्पादक है। ये किसान ही आज मोटे अनाज उगाकर अपनी आर्थिक स्थिति को बेहतर बना रहे हैं, बल्कि देश के विकास और सम्मान में अहम रोल अदा कर रहे हैं।

प्रदेश में अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 में विभागों के काय निर्धारित

मोटे अनाज के उपयोग को प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगे

समन्वित प्रयास कर मोटे अनाज के उपयोग को बढ़ावा दिया जायेगा

जागत गांव हमार, भोपाल।

मध्यप्रदेश में मोटे अनाज (मिलेट) के उपयोग को बढ़ावा देने के लिये विभिन्न विभागों के कार्य निर्धारित कर दिये गये हैं। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष 2023 में विभिन्न विभाग समन्वित प्रयास कर आम जनता में मोटे अनाज के उपयोग को प्रोत्साहित करने का कार्य करेंगे। जनवरी से दिसम्बर 2023 तक मोटे अनाज के उपयोग को अधिक से अधिक बढ़ावा देने के लिये विभागीय स्तर पर गतिविधियां की जायेंगी। इसके लिये विभागीय गतिविधियां भी निर्धारित की गई हैं। मध्यप्रदेश पर्यटन विभाग, पर्यटन विकास के लिए होटलों में मिलेट आधारित व्यंजनों का प्रचार-प्रसार करेगा। फूड फेस्टिवल और रोड-शो का आयोजन करेगा। एमपीटीसी होटलों में मिलेट प्रदर्शनी, फूड गैलरी और सोवेनियर शॉप की व्यवस्था होगी। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष में प्रदेश में किसान-कल्याण तथा कृषि विकास विभाग कृषि उपज मण्डियों, कृषि विभाग के कार्यालयों तथा संबंधित विभागों में बैनर, पोस्टर, फ्लेक्स तथा दीवार-लेखन से प्रचार-प्रसार करेगा। साथ ही राज्य स्तरीय मिलेट प्रतियोगिता का आयोजन भी करेगा। उद्यानिकी एवं खाद्य प्र-संस्करण और मध्यप्रदेश राज्य विपणन बोर्ड मिलेट प्र-संस्करण इकाइयों का प्रचार-प्रसार, विपणन गतिविधियों को बढ़ावा देना, सेमीनार, वर्कशॉप और अन्य कार्यक्रम करेगा। मध्यप्रदेश राज्य जैविक प्रमाणीकरण बोर्ड मिलेट फसलों के जैविक प्रमाणीकरण के लिये जागरूकता कार्यक्रम चलाएगा।

आयात-निर्यात की संभावनाओं पर कार्यक्रम

अंतराष्ट्रीय मिलेट वर्ष में कृषि और प्र-संस्कृत खाद्य उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एपीडा) मिलेट आधारित उत्पादों के प्र-संस्करण एवं आयात-निर्यात की संभावनाओं पर कार्यक्रम करेगा। राज्य स्तरीय कृषि विस्तार एवं प्रशिक्षण संस्थान मिलेट आधारित प्रशिक्षण कार्यक्रम करेगा। कृषि अभियांत्रिकी एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालय अपने कार्य क्षेत्र में आने वाले कृषि विज्ञान केन्द्रों, आत्मा, कृषि अभियांत्रिकी द्वारा मिलेट आधारित वेबीनार, सेमीनार, मूल्य संवर्द्धन, मिलेट प्र-संस्करण तथा मेकेनाइजेशन आधारित प्रशिक्षण-सह-कार्यशाला करेंगे। कृषि विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में मिलेट आधारित व्याख्यान, संभाग स्तरीय वर्कशॉप और प्रक्षेत्र दिवस के कार्यक्रम होंगे। मृदा परीक्षण एवं मृदा स्वास्थ्य कार्ड तैयार करने के साथ कोदो-कुटकी के लाभ संबंधी आलेख प्रकाशित किए जाएंगे।

आंगनवाड़ी कार्यकर्ता करेंगे जागरूक

पंचायत एवं ग्रामीण विकास, महिला-बाल विकास और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मिलेट उत्सव सप्ताह का आयोजन और मिलेट आधारित गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करेंगे। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता मिलेट को आहार में शामिल करने के लिये लोगों को जागरूक करेंगे। मध्यान्ह भोजन में मिलेट व्यंजनों को शामिल करने के लिये आंगनवाड़ी के माध्यम से लोगों को प्रोत्साहित करेंगे। महिला-बाल विकास विभाग व्यंजन प्रतियोगिताओं से मिलेट गतिविधियों का प्रचार-प्रसार करेगा। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग 26 जनवरी, 15 अगस्त और 2 अक्टूबर 2023 को ग्राम-सभाओं में मिलेट को भोजन में शामिल करने के लाभों पर चचाऊ करायेगा और मिलेट के प्रचार-प्रसार के लिये सभाओं तथा चौपालों का आयोजन कर साहित्य वितरित करवायेगा।

छात्रावासों में सप्ताह में एक दिन मिलेट व्यंजन परोसे जाएंगे

मध्यप्रदेश ग्रामीण आजीविका मिशन, किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) को प्रोत्साहित करने के लिये कार्यक्रमों का आयोजन करेगा। आदिम-जाति कल्याण विभाग द्वारा अनुसूचित जनजाति एवं अनुसूचित जाति वगऊ के लिये संचालित छात्रावासों में सप्ताह में एक दिन मिलेट व्यंजन परोसे जायेंगे। लघु, सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यम, मिलेट आधारित स्टार्ट-अप एवं उद्योगों के विकास के संबंध में कार्यक्रम किये जायेंगे।

हर स्तर पर मोटे अनाज के प्रसार-प्रसार का प्रयास होगा

अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्षमें स्कूल शिक्षा एवं उच्च शिक्षा विभाग स्कूलों में मिलेट आहार के लाभ के संबंध में माह में एक व्याख्यान करेगा। स्थानीय विद्यालयों में मिलेट वर्ष में मोटे अनाजों के उपयोग के लिये विभिन्न गतिविधियां की जायेंगी। मोटे अनाज के विस्तृत प्रचार-प्रसार के लिये अन्य विभागों के साथ जनसम्पर्क दूरदर्शन, आकाशवाणी, प्रिंट-इलेक्ट्रॉनिक-रेडियो और डिजिटल केम्पेनिंग का समग्र प्रयोग करेंगे।

प्रतिदिन पौध-रोपण अत्यंत सराहनीय पहल: केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री शेखावत

जल सम्मेलन में आए प्रतिभागियों ने लगाए पौधे

स्मार्ट सिटी पार्क अब वॉटर विजन पार्क होगा: शिवराज सिंह चौहान

जागत गांव हमार, भोपाल।

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जनता की भागीदारी से अनेक अभियान सफल हुए हैं। प्रदेश में पर्यावरण संरक्षण के लिए नागरिकों की सहभागिता निरंतर बढ़ रही है। नर्मदा जयंती वर्ष 2021 से प्रारंभ प्रतिदिन पौधे लगाने का संकल्प अन्य लोगों के लिए प्रेरणा बन रहा है। पौध-रोपण लोगों के स्वभाव में शामिल हो रहा है। स्वयं और परिजन की जन्म और विवाह की वर्षगांठ, परिवार के दिवंगत सदस्य की पुण्य-तिथि पर पौधा लगाने का कार्य नागरिक करने लगे हैं। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि जब किसी कार्य से आमजन जुड़ जाए तो उसे सफलता मिलती है। जब जनता के मन में बात बैठ जाती है तो उसे साकार होने में देर नहीं लगती। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कहा कि भोपाल में जल सम्मेलन में आए केंद्रीय मंत्रियों, राज्यों के मंत्रियों और अन्य प्रतिभागियों द्वारा आज श्यामला हिल्स स्थित स्मार्ट सिटी पार्क में किया गया पौध-रोपण वॉटर विजन 2047 (जल सम्मेलन) की स्मृति को बनाए रखने का प्रयास है। इस संकल्प की सिद्धि के लिए अब इस पार्क का नाम 'वाटर विजन पार्क' किया जाएगा। आज कचनार, हरसिंगार और आम के साथ ही अन्य कई प्रजातियों के पौधे लगाए गए। यह पार्क और आज का पौध-रोपण नागरिकों को पर्यावरण की रक्षा के लिए कार्य करने की प्रेरणा देगा। मध्यप्रदेश में वृक्ष-वीर और वृक्ष-वीरांगना पुरस्कार भी दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री श्री चौहान ने कलेक्टर भोपाल को इस उद्यान में आज पौध-रोपण में शामिल हुए जल सम्मेलन के प्रतिभागी केन्द्रीय मंत्रियों और राज्यों के मंत्रियों के उल्लेख के साथ जानकारी प्रदर्शित करने के निर्देश दिए।

पानी की निर्बाध आपूर्ति पर की गई गहन मंत्रणा: जल शक्ति मंत्री

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के वर्ष 2047 के विकसित भारत के संकल्प के अंतर्गत देश में पहली बार पानी के लिए काम करने वाले जन-प्रतिनिधियों और वरिष्ठ अधिकारियों का सम्मेलन भोपाल में हुआ। सम्मेलन में आए प्रतिनिधि मुख्यमंत्री श्री चौहान की प्रतिदिन पौधा लगाने की अनूठी पहल से जुड़ कर पौधा लगा रहे हैं। जल सम्मेलन में पानी की निर्बाध आपूर्ति हो, इस बारे में गहन मंत्रणा हुई है। सम्मेलन में जमीन, जलवायु, जंगल और जल के संरक्षण के लिए सभी एकजुट हों। इन प्राकृतिक संसाधनों को परिपुष्ट कर आने वाली पीढ़ी को संतुलित जीवन देने के संबंध में विचार-विमर्श हुआ। आज भोपाल के जल सम्मेलन के प्रतिभागियों को पौधा लगाने का अवसर मिला। यह अपनी तरह का पहला सम्मेलन था, जिसकी स्मृति को ताजा बनाए रखने के लिए यह उद्यान स्मृति वन के रूप में पहचान बनाकर हमें भी सम्मेलन की याद दिलाएगा। पौध-रोपण में केन्द्रीय जलशक्ति और खाद्य प्र-संस्करण उद्योग राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल, मप्र के जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी राज्य मंत्री बृजेन्द्र सिंह यादव के अलावा राज्यों के मंत्रियों में मिथलेश कुमार ठाकुर झारखंड, पीयूष हजारिका असम, स्वतंत्र देव सिंह उत्तर प्रदेश, कुंवर जी भाई भावलिया और मुकेश पटेल गुजरात, सुभाष ए. शिरोडकर गोवा, हरजीत सिंह बैंस पंजाब, अवांगबो नेवमाई मणिपुर शामिल थे।

आवासहीनों को आवासीय भू-खण्ड का मालिक बनाएगी प्रदेश सरकार: राजस्व मंत्री

प्रदेश में 1 लाख 28 हजार 160 पात्र परिवारों को आवास के लिए भूखंड देगी सरकार

जागत गांव हमार, भोपाल।

प्रदेश की जनता के सर्वांगीण विकास में जुटी राज्य सरकार लगातार प्रयास में जुटी है। नये साल में आवासहीनों को एक बड़ा तोहफा दिया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में टीकमगढ़ में हितग्राहियों को भू-स्वामी अधिकार-पत्र वितरित किये गए। इस योजना के तहत 2023 तक सभी आवासहीनों का खुद के घर का सपना सरकार साकार करेगी। राजस्व एवं परिवहन मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने बताया कि राज्य सरकार ऐसे लोगों को आवासीय भू-खण्ड उपलब्ध कराने जा रही है, जिनके पास खुद का आवास नहीं है। ऐसे आवासहीनों को मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना के तहत भू-खण्ड का पट्टा प्रदान किया जायेगा। राजस्व मंत्री श्री राजपूत ने बताया कि राजस्व विभाग द्वारा पूरे मप्र में आज की स्थिति में 87 हजार 603 भूमि स्वामी अधिकार पत्र तैयार कर लिए गए हैं। पूरे प्रदेश में 1 लाख 28 हजार 160 पात्र परिवार चिन्हित किये गए हैं। प्रदेश में जिनके पास रहने के लिए आवासीय भू-खण्ड नहीं है, उन जरूरतमंदो को भू-खण्ड उपलब्ध कराने का कार्य प्रदेश की सरकार करेगी।

योजना की पात्रता

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने बताया कि योजना में आवेदक परिवार पात्र होंगे, जिनके पास स्वतंत्र रूप से आवास नहीं है। आवेदक-परिवार के पास 5 एकड़ से कम भूमि हो, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिये पात्रता पर्ची हो, परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदाता न हो और कोई सदस्य शासकीय सेवा में होना चाहिए। इसके साथ ही आवेदक का नाम उस ग्राम में जहां वह आवासीय भू-खण्ड चाहता है, वहां 1 जनवरी, 2021 तक की मतदाता सूची में दर्ज होना चाहिए। इस योजना में पात्र आवेदकों के लिए आवासीय पट्टा वितरण की पूरी प्रक्रिया आनलाईन माध्यम से की गई है। सारा पोर्टल के माध्यम से 30 सितम्बर 2022 तक राजस्व विभाग द्वारा प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई करते हुए पूरे प्रदेश में कुल 1 लाख 28 हजार 160 पात्र परिवार चिन्हित किये गए हैं। इनको आवासीय भू-खण्ड प्रदान करने की शुरूआत की जा रही है।

गायों को वापस गांव, घर और खूंटे तक लाने की जरूरत

डॉ. सत्येन्द्र पाल सिंह
प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख
कृषि विज्ञान केंद्र, लहार (भिण्ड) म.प्र.

भारतीय समाज में पुरातन काल से ही गाय खासकर भारतीय गाय का बहुत ही पूज्यनीय स्थान रहा है। आदिकाल से लेकर आधुनिक भारत तक के सफर में भारतीय गायों का योगदान कम नहीं आंका जा सकता है। लेकिन मशीनी करण के दौर ने हमारी भारतीय गायों को जहां बेकार बना दिया वहीं कुछ पुरानी सरकारी नीतियों के कारण आज भारतीय गाय बेकार और लाचार और बेबस हो चली है।

जिस दौर में देश में हरित क्रांति की बात हो रही थी लगभग उसी दौर में हमारी भारतीय गायों को हटाने की बात की शुरुआत हुई। विदेशी सांड़ो का सीमन तथा विदेशों से सांड़ो को लाकर भारतीय नस्ल की गायों के साथ क्रॉस ब्रीडिंग की शुरुआत हुई। यह क्रॉस ब्रीडिंग की शुरुआत उस दौर में बहुत महत्वपूर्ण मानी जाती थी। देश में जब क्रॉस ब्रिल्डिंग की शुरुआत हुई उस समय शंकर गायों को बढ़ावा देने के लिए एक नारा दिया गया था कि देशी गाय से शंकर गाय, अधिक दूध और अधिक आय। लेकिन आज पिछले कुछ सालों से शंकर गायों को देश और भारतीय समाज से हटाने की बात हो रही है। भारत सरकार 'गोकुल मिशन' के माध्यम से भारतीय नस्ल की गायों के संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कार्यकर रही है।

इस के चलते एक बार पुन: भारत में भारतीय गायों का महत्व बढ़ रहा है। इन सबके चलते भारतीय गायों के संरक्षण की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं। भारत सरकार भी पिछले आठ सालों से भारतीय गायों की नस्लों को बचाने के लिए भरसक प्रयास कर रही है और उनको बढ़ावा दे रही है। इसी दिशा में आज एक बार पुन: प्राकृतिक कृषि की बात हो रही है। प्राकृतिक कृषि में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वह भारतीय नस्ल की देशी गाय ही है। प्राकृतिक कृषि में प्रयोग होने वाले जो उत्पाद तैयार होंगे वह भारतीय देशी गाय के गोमूत्र और गोबर से ही तैयार किए जाने हैं। इसको देखते हुए कहा जा सकता है कि भारतीय गाय की नस्लों यानी कि देशी गाय का महत्व बढ़ता दिखाई दे रहा है। इसको देखते हुए आज यह बात कही जा सकती है कि शंकर गाय से देसी गाय, अधिक टिकाऊ और अधिक आय। आज जब भारतीय देशी गाय की बात की जा रही है तो हम देखते हैं कि हमारी देशी गाय बहुत बड़े पैमाने पर गांव, शहरों और महानगरों में आवारा घुमंतु बनकर घूम रही हैं। भारतीय देशी गायों की दुर्दशा किसी भी से छुपी नहीं है। इन घुमंतू गायों को बचाने के लिए कई सरकारी प्रयास भी किए जा रहे हैं कई समाजसेवी संस्थाएं भी काम कर रही हैं परंतु यह प्रयास ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही है। जब तक आम जनमानस खासकर गांव-किसान में इन गायों के संरक्षण के लिए भाव नहीं पैदा होगा, तब तक इन घुमंतू आवारा गायों का संरक्षण नहीं हो सकता है। यह बात थोड़ी कड़वी जरूर है, परंतु अक्षरस सत्य है कि आज जो आवारा गायें घूमती हुई हमें खेत-खलियान और गांव-कस्बों से लेकर महानगरों में दिखाई दे रही हैं यह हमारे किसानों द्वारा छोड़ी हुई ऐसी गाये हैं जिन को किसानों ने कम दूध देने के कारण तथा खेती में उनके बच्चे काम ना आने के कारण इन्हें आवारा छोड़ छोड़ दिया है। आज यही दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो रही हैं। प्राकृतिक खेती में इन आवारा-घुमंतू गायों का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है।

प्राकृतिक कृषि में इन घुमंतू गायों का योगदान बहुत महत्वपूर्ण है। आज गौ आधारित प्राकृतिक कृषि की बात की जा रही है। प्राकृतिक कृषि से घुमंतू भारतीय गोवंश के संरक्षण की दिशा में एक नई आशा की किरण जगी है। यदि प्राकृतिक कृषि की पहल आम किसान-गांव से लेकर खेतों और फसलों तक पहुंचती है तो निश्चित रूप से देशी भारतीय गायों को दिन अच्छे लाए जा सकते हैं। अब यही समय है

कि घुमंतू गायों को वापस गांव, घर और खूटे तक लाने की जरूरत है। प्राकृतिक कृषि में घुमंतू देशी गाय का महत्वपूर्ण स्थान हो सकता है।

बताया जाता है कि घुमंतू देशी गाय के गोबर में पालतू देसी गाय से भी ज्यादा सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं। अत: ऐसे किसान जिनके पास आज देशी गाय नहीं है वह भी घुमंतू देशी गाय को पकड़कर प्राकृतिक खेती की शुरुआत कर सकते हैं। इससे जहां घुमंतू देशी गायों को नया जीवनदान मिलेगा वहीं इनको भरपेट चारा भी मिल सकेगा। किसानों की आमदनी में इजाफा होने के साथ ही उनके खेतों की मिट्टी की दशा और दिशा में सुधार होगा। किसानों का इस प्रकार का कदम देशी गाय की रक्षा के साथ ही प्राकृतिक कृषि को बढ़ावा देगा। इसलिए किसानों को इस दिशा में गंभीरता से विचार करने के साथ ही इसे जितनी जल्दी हो सके अपनाने की जरूरत है।

प्राकृतिक कृषि में किसान घुमंतू गायों का प्रयोग करते हैं तो यह उनके संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर सिद्ध हो सकता है। आज घुमंतू गायों के संरक्षण की बहुत नितांत आवश्यकता है। कुछ वर्षों पूर्व तक यही गौमाता अनाधिकृत रूप से कत्लखानों में काटी जा रही थी। लेकिन पिछले कुछ वर्षों से धर्म परायण सरकारों द्वारा गौ हत्या निषेध कानून का कड़ाई से पालन कराए जाने के कारण अब काफी कुछ हद तक गाय और नंदी की क्रूरतम हत्याओं पर पाबंदी लगी है। गौर करें तो गौ माता की कत्लखाना में हत्या पर पाबंदी जरूर लगी है, लेकिन इनके प्रति क्रूरता आज भी जारी है। गांव-शहरों में घूमती लाचार-बेचारी गायों को घायल, बीमार और भूखी, प्यासी बखूबी देखा जा सकता है। गायों के संरक्षण के लिए सरकारों के अलावा स्वयंसेवी संस्थाओं द्वारा काम भी किया जा रहा है। गौशालाओं में आवारा घुमंतू गोवंश के संरक्षण के प्रयास भी हो रहे हैं। कई राज्य सरकारों द्वारा गौशालाओं को अनुदान भी दिया जा रहा है। परंतु गायों की खिलाई-पिलाई, हारी-बीमारी, रखरखाव को देखते हुए यह अनुदान ऊंट के मुंह में जीरे के समान ही प्रतीत होता है। हालांकि कुछ राज्य सरकारों के द्वारा गौ संरक्षण की दिशा में अच्छी पहल की जा रही है। इन सब प्रयासों के बाद भी आज गांव, खेतों से लेकर शहरों, महानगरों और सड़कों पर इन गोवंश के झुंड के झुंड देखे जा सकते हैं। सरकारों की पहल भी बड़ी तादाद में घुमंतु गोवंश को पूरा संरक्षण नहीं दे पा रही है। देखा जाए तो सरकारी प्रयासों से यह पूरी तरह संभव भी नहीं हैं। इसके लिए आम जन भागीदारी खासकर किसानों की भागीदारी बहुत जरूरी है। आज चारे-दाने की कीमतें आसमान छू रही हैं। ऐसे में आवारा घुमंतू देशी भारतीय गोवंश की सुरक्षा के साथ उनसे प्राप्त गोबर और गोमूत्र की उजाड़ का कैसे सदुप्रयोग करें, इस दिशा में हमारे देश के किसानों को आगे आकर पहल करने की जरूरत है। इसके लिए आज सबसे अच्छा विकल्प प्राकृतिक कृषि के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। गाय बचेगी तो गांव बचेंगे और गांव बचेगा तो गरीब बचेगा। जिन्हें आज हम आवारा, घुमंतू, छुट्टा गाय कह रहे हैं कभी यही गायें भारतीय कृषि की रीढ़ रही हैं। मशीनीकरण के दौर और कम उत्पादक होने के कारण भारतीय गायों की नस्लों को हम और आपने आवारा बना कर छोड़ दिया है जो कि दर-दर की ठोकर खाती हुई घूम रही है।

मप्र में कृषि और खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में मौजूद अपार संभावनाएं

निरंतर बढ़ती आबादी के पोषण के लिए उसी अनुपात में फसलों का उत्पादन, कृषि गतिविधियों और खाद्य व्यापार में वृद्धि जरूरी हो जाती है। दुनिया में आबादी लगातार बढ़ रही है और वर्ष 2050 तक इसके 10 अरब तक पहुंचने का अनुमान है। वैश्विक कृषि बाजार वर्ष 2022 में 11 ट्रिलियन डॉलर से बढ़ कर 12.1 ट्रिलियन डॉलर हो गया हैं जो वर्ष 2026 तक 16.67 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच जाने की उम्मीद है।देश के दिल में बसा मध्यप्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है। इसकी जीएसडीपी में कृषि का योगदान 47 फीसदी है। इसीलिए मप्र को फूड बास्केट ऑफ इंडिया कहलाने का गौरव मिला है।

मध्य प्रदेश को 7 बार कृषि कर्मण पुरस्कार मिला है। इसी के मद्देनज़र प्रदेश में कृषि और खाद्य प्र-संस्करण क्षेत्र में अपार संभावनाएं मौजूद हैं।

मध्यप्रदेश देश में संतरा, मसाले, लहसुन, अदरक, चना और दालों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। राज्य में जैविक उत्पादों की खेती का रकबा भी अच्छा खासा है। सोयाबीन, गेंहूं मक्का, खट्टे फल, प्याज और फूलों का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। तिलहन, बागवानी, मिचज़, सुगंधित, औषधीय पौधों और दुग्ध का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। शरबती गेहूं का सर्वाधिक उत्पादक और निर्यातक है। शरबती गेहूं का आटा देश में उच्चतम गुणवत्ता वाला माना गया है। मध्यप्रदेश में बेहतर बीज गुणवत्ता के विकास, उर्वरकों, चारा उत्पादन और आपूर्ति, कृषि मशीनरी और उपकरणों के निर्माण और सिंचाई परियोजनाओं में पूंजी निवेश पर विशेष ध्यान देने के साथ ही खेती के क्षेत्र में निवेश के लिए बहुत सारे मौके हैं। साथ ही कृषि और खाद्य प्र-संस्करण मूल्य श्रंखला में मौजूदा चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य आर्टिफिशयल इंटेलिजेंस (एआई), ब्लॉकचेन और संबंधित डिजिटल सेवाओं को भी प्रदेश में प्रोत्साहित किया जा रहा है।

खाद्य प्र-संस्करण: मध्यप्रदेश सरकार ने मेगा फूड पार्क, कृषि प्र-संस्करण क्लस्टर, एकीकृत कोल्ड चेन और मूल्य संवर्द्धित अवसंरचना, खाद्य प्र-संस्करण और संरक्षण क्षमताओं को बढ़ाने की पहल की है। कृषि, खाद्य और डेयरी प्र-संस्करण क्षेत्र को बढ़ाने के लिये भी कई कार्य किये जा रहे हैं। सूक्ष्म खाद्य प्र-संस्करण के पीएम फॉर्मलाइजेशन की केन्द्र सरकार की पहल, राज्य उद्यमियों की क्षमता निर्माण और किसान उत्पादक संगठनों, स्व-सहायता समूहों को सहायता देने, असंगठित सूक्ष्म खाद्य प्र-संस्करण उद्यमों की चुनौतियों का सामना करने के लिए राज्य सरकार काम कर रही है।

राज्य में 8 स्थान पर सरकारी वित्त-पोषित फूड पार्कों की स्थापना, 2 निजी मेगा फूड पार्क और एपीसी के तहत अनुमोदित 4 कृषि प्र-संस्करण क्लस्टर जैसी कई पहल की गई है। राज्य ने अपनी भण्डारण क्षमता को लगभग 15 मिलियन मीट्रिक टन तक बढ़ा दिया है और यहां 3 लाख 54 हजार वगज्मीटर की कुल सीमा के साथ एक विशाल कोल्ड-स्टोरेज हैंडलिंग क्षेत्र है।

एक जिला-एक उत्पाद योजना में मप्र ने 24 कृषि और बागवानी से संबंधित प्राथमिक उत्पादों की पहचान की है। कोदो-कुटकी, बाजरा, संतरा/साइट्रस, सीताफल, आम, टमाटर, अमरूद, केला, पान, आलू, प्याज, हरी मटर, मिर्च, लहसुन, अदरक, धनिया, सरसों के उत्पाद, गन्ना उत्पाद, आँवला और हल्दी इसमें शामिल हैं। संतरे का उत्पादन प्रदेश को संतरा प्र-संस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए आदशज़ बनाता है। प्रदेश में बैतूल, कटनी, अनूपपुर, रीवा, सिंगरौली और रायसेन जिले में आम आधारित कई खाद्य प्र-संस्करण उद्योग स्थापित होने के विभिन्न चरण में हैं।

मध्यप्रदेश तीसरा सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक राज्य है। दुग्ध उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। देश के कुल दुग्ध उत्पादन में प्रदेश का 8.6 प्रतिशत का योगदान है। मध्यप्रदेश सहकारी डेयरी फेडरेशन- शीर्ष निकाय एमपीसीडीएफ की अकेले 9 लाख 13 हजार केजीपीडी की औसत दूध खरीद दर्ज की गई है। डेयरी प्र-संस्करण में शामिल प्रमुख कंपनी-उपक्रमों में अमूल सांची, अनित इंडस्ट्रीज सौरभ और पवनश्री फूड इंटरनेशनल शामिल हैं। कुल मिलाकर राज्य में समग्र कृषि, खाद्य और डेयरी प्र-संस्करण मूल्य श्रंखला में निवेश के भरपूर अवसर है।

सकल वन फूल रही सरसों

सरसों के पीले फूलों से धरती इन दिनों जगह जगह आच्छादित दिखाई दे रही है । अमीर खुसरो की बंदिश याद आती है- सकल वन फूल रही सरसों। कृषि का इतिहास व सेन्टर आफ ओरीजिन की जानकारी रखने वाले विद्वान बताते हैं कि आज जो सब्जियां प्रचलन में है उनमें से ज्यादातर भूमध्यसागर या मेडीटेरनियन के आसपास से आयीं। सत्यजीत राय की चारुलता का नायक मेडिटेरेनियन शब्द सुनते ही कल्पना लोक में डूब जाता है। उसे जाने कितने लेखक - कवि याद आने लगते हैं।

जो पुर्तगाली मसालों की खोज में भारत आये थे वे हमें अनन्नास, पपीता, अमरूद दे गये । आलू को कोलम्बस दक्षिण अमरीका से योरप लाया और सर टामस रो पहली बार भारत में जहांगीर के दरबार में लेकर हाज़िर हुआ। टमाटर योरप से आया और रमास को छोड़कर अन्य बीन्स कही जाने वाली कुछ सब्ज़ियां भी। गोभी की तीनों किस्मों ने भूमध्यसागर के तट से भारत की यात्रा की । फूलगोभी, बंदगोभी और गांठगोभी । ये तीनों उसी

ब्रेसिका कुल की हैं जिसकी एक सदस्य सरसों हैं। तो क्या सरसों भी योरप से भारत आयी? अगर ऐसा होता तो तेरहवीं सदी में अमीर खुसरो सरसों को देखकर कैसे प्रसन्न हो रहे होते। हालांकि चंबल के बीहड़ों में जब सरसों की खेती शुरू नहीं हुई थी उससे पहले तिलहन के रूप में सोंहां की खेती बड़े पैमाने पर जाड़ों में होती थी। Near शब्द को हम अंग्रेजी का मानते हैं। अगर ऐसा होता तो अंग्रेजों के भारत आने से पहले गोस्वामी तुलसीदास कैसे लिख रहे थे कि ऋष्यमूक पर्वत नियराई । कबीर को भी पता था निन्दक नियरे राखिये आंगन कुटी छवाय । सरसों भी इसी तरह अमीर खुसरो के समय में सकल वन फूल रही होगी।

-जयंत सिंह तोमर, विभाग अध्यक्ष,
आईटीएम युनिवर्सिटी ग्वालियर

पशु ऋण दिला रहा दुग्ध संघ, तो 90 प्रति तक अनुदान देगा पशुपालन विभाग

प्रदेश में दूध उत्पादन बढ़ाने की मशक्कत में जुटे सरकारी संस्थान

जागत गांव हमार, भोपाल।

बच्चों, बीमारों और बुजुर्गों के लिये जरूरी दूध की बढ़ती कीमतों को देखते हुए जनता जहां सकते में है। वहीं दूसरी ओर जिम्मेदारी संभाल रहे सरकार के संस्थान भी चिंता में आ गये हैं। लिहाजा पशुपालन व दुग्ध संग्रहण से जुड़े यह संस्थान कीमतों को स्थिर रखने की चुनौती से निपटने उत्पादन बढ़ाने के प्रयास में जुट गये हैं। इसके मद्देनजर दुग्ध संघ जहां किसानों को ऋण गारंटी दे रहा है। वहीं पशुपालन विभाग 90 प्रतिशत तक अनुदान देने की तैयारी में है। यह स्थिति तब सामने आई है जबकि दूध उत्पादन के मामले में मप्र ने बीते सालों में काफी प्रगति की है। आंकलन इसी से किया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश और राजस्थान के बाद देश में मप्र तीसरे स्थान पर है। यहां पर प्रति व्यक्ति दूध की उपलब्धता 545 ग्राम प्रतिदिन हो गई है। यह राटीय औसत से 406 ग्राम ज्यादा है। बावजूद इसके दूध की कीमतें घटने के बजाय यहां बढ़ी है। इसके पीछे डीजल के दामों में हुई वृद्धि और गेंहू हार्वेस्टिंग के बीच बढ़े निर्यात का असर माना जा रहा है। जिससे पशुओं के लिये जरूरी चारे और दाने पर मंहगाई की मार पड़ी है और इसकी भरपाई के लिये किसानों ने दाम बढ़ा दिये हैं। लिहाजा पशुपालन विभाग सहित दुग्ध संग्रहण और विपणन से जुड़े सरकार के उपक्रम दूध की कीमतें स्थिर करने पर जोर देने लगे हैं। यह बात अलग है कि भोपाल सहकारी दुग्ध संघ ने इसके मद्देनजर पशुपालकों को दुधारू जानवर खरीदी प्रोत्साहन के लिये जहां पहले से ऋण मुहैया कराने गारंटर बन रहा है। वहीं अब यह लाभांवितों की संख्या बढ़ाने जा रहा है। जबकि पशुपालन विभाग पूर्व में प्रचलित योजनाओं डेयरी प्लस, आचार्य विद्यासागर योजना के साथ अब जनजातियों के लिये 90 प्रतिशत तक अनुदान देने की तैयारी में है। इसके तहत 1300 से अधिक गौवंश खरीदवाने का लक्ष्य रखा गया है। जबकि इसके पहले विद्यासागर योजना के तहत 313 डेयरी और डेयरी प्लस के तहत 3500 जानवरों का लक्ष्य इस मार्च तक पूरा करने पर जोर दे रहा है।

3 करोड़ के ऋण दिला चुके हैं

भोपाल के सांची दुग्ध मर्यादित अब तक 3 करोड रूपये के ऋण वितरित करा चुका है। सांची दुग्ध संघ के सीईओ आरपीएस तिवारी ने बताया कि एसबीआई के सहयोग से यह कार्य किया जा रहा है। कोशिश यह है कि यदि ऋण गारंटी मिल जाएगी तो बैंक पशुपालकों को सहज रूप से ऋण वितरित कर सकेंगे।

90 प्रतिशत तक देंगे अनुदान

पशुपालन विभाग के संचालक डॉ आरके मेहिया बताते हैं कि दुग्ध की मांग व आपूर्ति को ध्यान में रखकर पशुपालकों के लिये 90 प्रतिशत तक अनुदान देने की योजना बनाई गई है। हालांकि इसका लाभ विशेष पिछ?ी जनजातियों में शामिल सहरिया, भारिया और बैगा जनजातियों को गौवंश सहित दूसरे दुधारू पशु खरीदने के लिये दिया जाएगा। इससे दूध उत्पादन जहां बढ़ेगा, वहीं कीमतें भी स्थिर रहेंगी।

18 हजार टन दूध उत्पादन होने की संभावना

सरकार के प्रयासों को देखते हुए वित्तीय वर्ष 2021-22 में एक हजार टन से ज्यादा दूध उत्पादन बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। 2020-21 में यह 17,999 मिट्रिक टन रहा है। जबकि इसके पहले 2019-20 में यह 17,109 मिट्रिक टन तक सीमित था।

किसान के लिए वरदान बलराम तालाब योजना

देवास। सरकारी योजनाओं का यदि ईमानदारी से पालन किया जाए तो न केवल प्रगति होती है, बल्कि आमदनी भी बढ़ती है। ग्राम पंचायत बेहरी तहसील बागली जिला देवास के कृषक वि पिता हरि नारायण ने बलराम तालाब योजना का लाभ लिया। जिसका नतीजा यह रहा कि अब वे वर्ष में तीन फसलें लेने लगे हैं। रवि के पास 2 हेक्टेयर भूमि है। पानी का सीमित साधन होने से पूरा खेत सिंचित नहीं हो पाता था। जिससे खेत में उत्पादन कम मात्रा में प्राप्त होता था। इन्हें कृषि विभाग द्वारा किसान पाठशाला के माध्यम से कृषि विभाग की संचालित योजनाओं की जानकारी प्राप्त हुई। इसके बाद रवि ने कृषि विभाग से संपर्क कर बलराम तालाब योजना का लाभ लेकर तालाब खुदवाया। जिसमें कृषि विभाग से 80 हजार रूपये का अनुदान प्राप्त हुआ। अब पहले से उनके खेत में जो फसल बोई गई थी, उसका उत्पादन अतिरिक्त बनने लगा एवं पूरी जमीन सिंचित हो गई है। कृषक रवि कहते है कि एक से दो फसल की जगह तीन-तीन फसल करने लगा हूं।

दिल्ली से आए कृषि वैज्ञानिकों केले की फसल का किया निरीक्षण

बुरहानपुर। भारत सरकार द्वारा गठित वरिष्ठ वैज्ञानिकों के दल द्वारा केला फसल पर आ रही कुकम्बर मोजेक वायरस (सीएमवी) से ग्रसित केला फसल का गत दिनों निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कृषि अनुसंधान केन्द्र नई दिल्ली के वरिष्ठ वैज्ञानिक प्रोफेसर इद्रानीदास गुप्ता, डॉ.अमालेण्डू घोष, डॉ.सुधाकर श्रीवास्तव, डॉ. जी.पी.जगताप, डॉ.ए.टी.डाउन्डे, डॉ. नेहारकर, डॉ.कार्तिकेय सिंह, कृषि उपसंचालक एम.एस.देवके, उपसंचालक आर.एन.तोमर उपस्थित रहे।

उक्त दल द्वारा संयुक्त रूप से ग्राम इच्छापुर, दापोरा, चापोरा, शाहपुर अड़गाव, सिरसोदा, भातखेड़ा आदि क्षेत्र का भ्रमण कर कृषकों से चर्चा भी की गई तथा केला फसल में विगत दो वर्षोंं से आ रही सीएमवी वायरस बीमारी के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की। वहीं कृषकों के प्रक्षेत्र पर सीएमवी वायरस से ग्रसित केला फसल के सैंपल जांच हेतु एकत्रित किये गये।

आचार्य श्री विद्यासागर जीवदया गोसेवा सम्मान योजना में मिलेंगे पुरस्कार

इंदौर। पशुपालन विभाग के अंतर्गत गो-सेवा, गो-संरक्षण एवं जीवदया आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्थानों एवं व्यक्तियों को प्रोत्साहन एवं सम्मान प्रदान करने के लिए आचार्य श्री विद्यासागर जीवदया गो सेवा सम्मान योजना नवीन योजना के रूप में स्वीकृत की गई है। योजना अंतर्गत संस्थागत श्रेणी एवं व्यक्तिगत श्रेणी के पुरस्कार सम्मिलित किए गए हैं । वर्ष में एक बार इस योजना का लाभ लिया जा सकता है।

उप संचालक, पशु चिकित्सा सेवाएं ने बताया कि व्यक्तियों एवं संस्थानों के योजना के अनुसार प्राप्त आवेदन जिला गोपालन एवं

पशुधन संवर्धन समिति को प्रस्तुत करेंगे। जिला गोपालन पशुधन संवर्धन समिति संस्थागत श्रेणी एवं व्यक्तिगत श्रेणी अंतर्गत प्राप्त आवेदनों में से पात्र संस्था एवं व्यक्तियों का चयन कर प्रस्ताव पुरस्कार के लिए अनुशंसा करती है। उन्होंने बताया कि प्राप्त प्रस्तावों पर मध्यप्रदेश गोपालन एवं पशुधन संवर्धन बोर्ड की राज्य स्तरीय समिति की अनुशंसा के आधार पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले संस्थानों एवं व्यक्तियों का चयन कर संस्थागत श्रेणी एवं व्यक्तिगत श्रेणी के पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं ।

बताया गया कि संस्थागत श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कर में प्रथम पुरस्कार 5 लाख रूपए, द्वितीय पुरस्कार 3 लाख रूपए, तृतीय पुरस्कार 2 लाख रूपए और सांत्वना पुरस्कार की राशि रूपए 2 लाख जिसमें प्रति पुरस्कार 50 हजार के मान से दिए जाते है। उन्होंने बताया कि व्यक्तिगत श्रेणी के अंतर्गत पुरस्कार में प्रथम पुरस्कार एक लाख, द्वितीय पुरस्कार 50 हजार, तृतीय पुरस्कार 20 हजार दिया जाता है।

'हरा सोना' की खेती चमका सकती है किसानों की तकदीर

जागत गांव हमार, भोपाल।

खेती-किसानी को मुनाफे वाला काम बनाने की लगातार कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में ऐसे फसलों की खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है जो कम लागत में ज्यादा मुनाफा दे सकती हैं। ऐसे में किसानों के बीच बांस की खेती का चलन तेजी से बढ़ा है। राष्ट्रीय बांस मिशन के माध्यम से किसानों को बांस की खेती के लिए मदद की जा रही है। बांस की बुवाई के बाद आप इससे तकरीबन 40 से 60 साल तक मुनाफा कमा सकते हैं। खेती किसानी में इसे हरा सोना भी माना जाता है। इसके उपयोग से कार्बनिक कपड़े बनाए जाते हैं। इससे कई तरह के प्रोडक्ट भी बनाए जाते हैं। सजावटी सामानों को बनाने में भी बांस का उपयोग किया जाता है। मध्य प्रदेश, असम, कर्नाटक, नगालैंड, त्रिपुरा, उड़ीसा, गुजरात, उत्तराखंड व महाराष्ट्र आदि राज्यों में इसकी खेती बड़े स्तर पर की जाती है.

बांस की खेती के लिए ऐसे जमीन करते हैं तैयार

इसकी खेती के लिए जमीन तैयार करने की आवश्यकता नहीं होती है. बस इस बात का ध्यान रखें कि मिट्टी बहुत अधिक रेतीली नहीं होनी चाहिए। आप 2 फीट गहरा और 2 फीट चौड़ा गड्ढा खोदकर इसकी रोपाई कर सकते हैं. साथ ही बांस की रोपाई के समय गोबर की खाद का प्रयोग कर सकते हैं। रोपाई के तुरंत बाद पौधे को पानी दें और एक महीने तक रोजाना पानी देते रहें। 6 महीने के बाद इसे सप्ताह के सप्ताह पानी दें।

बुवाई से लेकर कटाई तक

बांस को बीज, कटिंग या राइज़ोम से लगाया जा सकता है। इसके बीज अत्यंत दुर्लभ और महंगे होते हैं। पौधे की कीमत बांस के पौधे की किस्म और गुणवत्ता पर भी निर्भर करती है। प्रति हेक्टेयर इसके करीब 1,500 पौधे लगते जा सकते हैं। प्रति पौधे 250 रुपये का खर्च आता है। बुवाई के 4 साल के बाद इसके पेड़ की कटाई शुरू होती है। 1 हेक्टेयर से आपको करीब 4 लाख रुपये तक का मुनाफा होता है। मुनाफे की ये प्रकिया 40 से 60 साल तक लगातार चलती है।

बदलते मौसम में आलू-टमाटर समेत सब्जियों वाली फसलों और दलहन-तिहलन में रोग और कीट लगने की आशंका

शीत लहर से फसलों एवं सब्जियों में कीट-व्याधियों एवं पाला से बचाव के लिए कृषि वैज्ञानिकों की सलाह

जागत गांव हमार, टीकमगढ़।

बदलते मौसम में आलू-टमाटर समेत सब्जियों वाली फसलों और दलहन-तिहलन वाली फसलों में रोग और कीट लगाने की आशंका बढ़ जाती है। मौसम में बदलाव के चलते शीत लहर और ठंडी हवाओं के चलने के साथ ही रबी की फसलों में झुलसा और पाला पड़ने की संभावना बढ़ जाती है, ऐसे में किसान कुछ बातों का ध्यान रखकर नुकसान से बच सकते हैं। शीत लहर और पाले का फसलों और फलदार वृक्षों की उत्पादकता पर सीधा प्रभाव पड़ता है। फूल आने और बालियां/फली विकसित होने के दौरान फसलों के पालाग्रस्त होने की सबसे अधिक संभावना होती है। पाले के प्रभाव से पौधों की पत्तियाँ एवं फूल झुलसने लगते हैं। जिससे फसल प्रभावित होती है। कृषि विज्ञानं केंद्र के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख डॉ. बी.एस. किरार, वैज्ञानिक डॉ. आर.के. प्रजापति, डॉ. यू.एस. धाकड़, डॉ. एस.के. सिंह, डॉ. एस.के. जाटव, डॉ. आई.डी. सिंह एवं जयपाल छिगारहा द्वारा शीत लहर से फसलों एवं सब्जियों में कीट-व्याधियों एवं पाला से बचाव हेतु तकीनीकी सलाह सलाह दी जा रही है। कुछ फसलें बहुत अधिक तापमान या पाला सहन नहीं कर पाती हैं, जिससे उनके खराब होने का खतरा रहता है। यदि पाले के समय फसल की देखभाल न की जाए तो उस पर आने वाले फल या फल झड़ सकते हैं। जिससे पत्तियों का रंग मिट्टी के रंग जैसा हो जाता है। यदि शीत लहर हवा के रूप में चलती रहती है तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है, लेकिन यदि हवा रुक जाती है तो पाला पड़ता है, जो फसलों के लिए अधिक हानिकारक होता है। पाले से सबसे ज्यादा नुकसान मटर, सरसों, धनिया के साथ मिर्च और बैंगन की फसल को होता है ठंड के कारण सब्जियों के पौधे काले पड़ जाते हैं। लेकिन कुछ उपायों से किसान ठंड के कारण अपनी फसल को खराब होने से बचा सकते हैं। कृषि विज्ञान केंद्र, टीकमगढ़ के प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख और पादप रक्षा वैज्ञानिक डॉ. आर.के प्रजापति बताते हैं, ये मौसम ही कीट और रोग लगने का है। मौसम ऐसा कि रोग और कीट बढ़ने के लिए अनुकूल है। आलू-टमाटर समेत दूसरी सब्जियों में झुसला रोग लग सकता है, पत्तियों के मुड़ने की प्रक्रिया, यानी रस चूसक भुनगे बहुत तेजी से लगेंगे।

फसलों को रोग व्याधियों से बचा सकता है नीम ऑयल का छिड़काव

कोशिश करें नीम ऑयल का छिड़काव करें, कंडे की राख का इस्तेमाल करें। येलो स्टिकी ट्रैप लगा लें और रोग वाले पौधों को दबा दें। दलहनी फसलों की बात करें तो चना, मटर, मसूर में जीवाणु झुलसा रोग, उकठा रोग, चने में फ्ली छेदक कीट अंडे दे रहे होंगे, सरसों की बात करें तो माहू है सफेद मक्खी है, थ्रिप्स का प्रकोप तेजी से बढ़ेगा नर्सरी के पौधों और सब्जियों की फसलों को बोरियों, पॉलिथीन या पुआल से ढक देना चाहिए। क्यारियों के किनारों पर हवा को रोकने के लिए बाड़ को हवा की दिशा में बांधकर फसल को पाला एवं शीत लहर से बचाया जा सकता है। पाले की संभावना को ध्यान में रखते हुए ज़रुरत पड़ने पर खेत की सिंचाई कर देनी चाहिए। इससे मिट्टी का तापमान कम नहीं होता है। सरसों, गेहूँ, चावल, आलू, मटर जैसी फसलों को पाले से बचाने के लिए सल्फ्यूरिक अम्ल (गंधक का तेजाब) के छिड़काव से रासायनिक सक्रियता बढ़ती है तथा पाले से बचाव के अलावा पौधे को लौह तत्व भी प्राप्त होता है। दीघज़्कालीन उपाय के रूप में फसलों की सुरक्षा के लिए शहतूत, शीशम, बबूल, खेजड़ी और जामुन आदि जैसे वायु अवरोधक वृक्षों को खेत की मेड़ों पर लगाना चाहिए, जो फसल को पाले और शीत लहरों से बचाते हैं।

पाले का असर कम करने के लिए क्या करें

500 ग्राम थायोयूरिया को 1000 लीटर पानी में घोलकर छिड़काव किया जा सकता है और 15 दिनों के बाद दोबारा छिड़काव करना चाहिए। क्योंकि सल्फर (गंधक) पौधे में गर्मी पैदा करता है, इसलिए प्रति एकड़ 8-10 किलो सल्फर डस्ट डाला जा सकता है। या 600 ग्राम घुलनशील गंधक को 200 लीटर पानी में मिलाकर प्रति एकड़ फसल पर छिड़काव करने से पाले का असर कम होता है। पाले के दिनों में मिट्टी की जुताई या जुताई नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से मिट्टी का तापमान कम हो जाता है। फसल बचाने के लिए सबसे जरुरी है कि प्रतिदिन खेती की निगरानी की जाए। अगर पौधे के पत्ते में रोग दिखाई दें, तुरंत उन्हें उखाड़कर जमीन में दबा दें। वो कहते हैं, ज्यादा रोग दिखे तुरंत विशेषज्ञों की सलाह लें और एहतियातन एक फफूंद नाशक का छिड़काव काबेंज़ाजिम मैनकोज़ेब या फिर मेटालैविसल और मैंकोजेब का छिड़काव कर दें। आलू की फसल में झुलसा के लिए अनुकूल मौसम है तो इन फंगीसाइड का 2 ग्राम प्रति लीटर में छिड़काव जरूर कर दें। सरसों की फसल में सफेद पत्ती धब्बा जो रोग लगता है उसमें 3 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलाकर कॉपर ऑक्सीक्लोराइड का छिड़काव का छिड़काव कर सकते हैं।

ज्यादा नमी भी नुकसानदायक

खेत में ज्यादा नमी होने पर सब्जियों वाली फसलों में खासकर नुकसान हो सकता है। कई रोग लग सकते हैं। कीटनाशक हो या रोग नाशक या फिर खरपतवार नाशक उनके छिड़काव का सबसे अच्छा मौसम होता है जब धूप खुली हो। अगर कोहरा है, बादल छाए हैं, बारिश की आशंका है तो कीटनाशक छिड़काव से भी परहेज करें। अगर फसल में फूल आ गए गए हैं तो किसी प्रकार के रासायनिक कीटनाशक के प्रयोग से बचें। डॉ. प्रजापति कहते हैं, जिस भी फसल में फूल आ रहे हैं वहां रासायनिक छिड़कावों का इस्तेमाल न करें। वनाज फूल की ग्रोथ (बढ़वार) रुक जाएगी। फूल झड़ जाएंगे, जिससे दाने और फल नहीं बन पाएंगे। ऐसे में प्राकृतिक तरीकों, धुआं, नमी, नीम का तेल और कंडों की राखा का इस्तेमाल करें। इसके अलावा खेत में मधुमक्खियां पाल रखी हैं, या वो उधर आती हैं तो दिन के वक्त रासायनिक छिड़काव न करें वर्ना वो मर जाएंगी।

मंडी बोर्ड के अधिकारियों द्वारा विभिन्न राज्यों में किए गए अध्ययन का प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया

विभिन्न राज्यों में किए गए मंडियों की विपणन व्यवस्था के अध्ययन का पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुतीकरण

भोपाल। दिनांक 6 जनवरी 2023 को म.प्र. राज्य कृषि विपणन बोर्ड (मंडी बोर्ड) भोपाल के सभागार में प्रबंध संचालक जी.व्ही.रश्मि के समक्ष मंडी बोर्ड के अधिकारियों द्वारा विभिन्न राज्यों में किए गए मंडियों की विपणन व्यवस्था के अध्ययन का पीपीटी के माध्यम से प्रस्तुतीकरण किया गया। उक्त प्रस्तुतीकरण में मुख्य रूप से सम्बंधित राज्य के एंड टू एंड कम्प्यूटराइजेशन प्रणाली का अध्ययन डिजिटल पेमेंट मंडी एक्ट का अध्ययन मंडी कमीशन एजेंट प्रणाली तथा मंडी शुल्क की दर ई-नेम के अंतर्गत लैबर ग्रेडिंग एंड सोर्टिंग यूनिट की स्थिति एवं अन्य कोई नवाचार आदि विषयों पर अध्ययन रिपोर्ट प्रस्तुत की गई।

- उत्तर प्रदेश राज्य के अध्ययन का प्रस्तुतीकरण एच. आर. लारिया संयुक्त संचालक रीवा द्वारा किया गया।
- हरियाणा राज्य के अध्ययन का प्रस्तुतीकरण आर. पी. चक्रवर्ती संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय ग्वालियर द्वारा किया गया।
- पंजाब राज्य के अध्ययन का प्रस्तुतीकरण एस. के. कुमरे संयुक्त संचालक आंचलिक कार्यालय सागर द्वारा किया गया।
- तमिलनाडु राज्य के अध्ययन का प्रस्तुतीकरण डॉक्टर आनंद मोहन शर्मा उपसंचालक आंचलिक कार्यालय जबलपुर द्वारा किया गया।
- राजस्थान राज्य के अध्ययन का प्रस्तुतीकरण प्रवीण वर्मा उप संचालक आंचलिक कार्यालय उज्जैन द्वारा किया गया।
- गुजरात राज्य के अध्ययन का प्रस्तुतीकरण नरेश परमार मंडी सचिव इंदौर द्वारा किया गया।
- अपर संचालक एस. बी. सिंह जी द्वारा मध्यप्रदेश राज्य के बाहर संचालित प्राइवेट मंडियों के अध्ययन के संबंध में अपना प्रस्तुतीकरण किया गया।

तुलनात्मक अध्ययन तैयार करने के निर्देश

उक्त बैठक में अपर संचालक डी.के. नागेंद्र, चंद्रशेखर वशिष्ठ, दिनेश द्विवेदी, चीफ प्रोग्रामर संदीप चौबे उपस्थित रहे। प्रबंध संचालक द्वारा समस्त अध्ययन रिपोर्टों का प्रस्तुतीकरण देखा जाकर मध्य प्रदेश तथा संबंधित राज्यों का तुलनात्मक अध्ययन तैयार करने के निर्देश देकर संबंधित राज्यों में जो कृषक हितैषी कार्य हो रहे हैं उसको भी अपनी विस्तृत रिपोर्ट में सम्मलित किए जाने के निर्देश दिए गए। उक्त भ्रमण पर भेजे जाने पर समस्त प्रतिभागियों द्वारा प्रबंध संचालक महोदया का धन्यवाद ज्ञापित किया। अंत में डी. के. नागेंद्र जी द्वारा आभार व्यक्त कर बैठक को समाप्त किया गया।

- मछली पालन के साथ सिंघाड़ा उत्पादन भी करेंगी

85 अमृत सरोवर, 70 गौशाला चलाएंगी महिला किसान

फोटो- अमृत सरोवर

मुरैना। आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में महिलाओं ने गैर परंपरागत क्षेत्र में कदम बढाए हैं। स्व-सहायता समूहों के माध्यम से यह महिलाएं तालाबों का प्रबंधन करेंगी। सिंचाई प्रबंधन के साथ इन तालाबों में महिलाएं मछली पालन, सिंघाड़ा उत्पादन सहित गौशाला संचालन के काम भी करेंगी। 12.68 करोड़ रुपए की लागत से केंद्र सरकार की अमृत योजना में बने 101 तालाबों से 85 का प्रबंधन महिलाओं को दिया जा चुका है, बाकी प्रक्रिया इस माह के अंत तक पूरी कर ली जाएगी। जिला पंचायत के सीईओ डॉ इच्छित गढ़पाले ने बताया कि अप्रेल 2022 में शुरू होकर इन तालाबों का निर्माण अगस्त तक 2022 में पूर्ण कर लिया है। अब इनका प्रबंधन केवल महिलाओं को दिया जा रहा है। 101 अमृत सरावरों में से 85 सरोवर महिलाओं को दिए गए हैं। इनमें 82 तालाबों से महिलाएं केवल सिंचाई प्रबंधन करेंगी और 11 तालाबों में मछली पालन किया जा रहा है। जबकि आठ तालाबों में सिंघाड़े की फसल उगाई जाएगी। 16 समूहों से भी स्व-सहायता समूहों का अनुबंध इस माह के अंत तक होने की उम्मीद है। इन तालाबों से जहां एक हजार 83 हेक्टेयर भूमि में सिंचाई हो सकेगी, वहीं 57 हेक्टेयर बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने में मदद मिलेगी। 101 अमृत सरोवरों में 17 लाख 91 हजार 310 क्यूबिक मीटर जल संग्रहण होगा। इससे पहाड़गढ़, जौरा, कैलारस एवं सबलगढ़ क्षेत्र में सिंचाई के अभाव में किसानों का पलायन भी रूकेगा।

जनहितकारी महिला स्वसहायता समूह की अध्यक्ष श्रीमती गीता ने बताया कि सिंचाई प्रबंधन के लिये हमारे समूह ने एक तालाब लिया है। रबी फसल में करीब 10 हैक्टेयर में सिंचाई होगी अगले साल मछली पालन सिंघाड़ा की खेती पर भी काम करेंगे।

जिला पंचायत के सीईओ डॉ. इच्छित गढ़पाले ने बताया कि 101 तालाबों में से 85 का प्रबंधन स्वसहायता समूहों को दिया गया है। इनसे सिंचाई के अलावा मछली पालन सिंघाड़ा उत्पादन के साथ बंजर भूमि को कृषि योग्य बनाने में सहायता मिलेगी। 135 तालाब और बनाकर महिला समूहों को दियो जायेंगे तो क्रांतिकारी परिवर्तन होगा। अभी तक जनपद अंबाह में 11, जौरा में 13, कैलारस में 8, मुरैना में 40, पहाड़गढ़ में 9, पोरसा में 9, सबलगढ़ में 11 इस प्रकार कुल 101 तालाबों का निर्माण किया गया है।

रामप्रसाद बिस्मिल को समर्पित किया तालाब

जनपद पंचायत अंबाह की ग्राम पंचायत खिरेंटा में कछपुरा के पास निर्मित अमृत सरोवर अमर शहीद पं रामप्रसाद बिसिमल को समर्पित किया गया है। इस तालाब में 15 हजार घन मीटर जल संग्रहण होगा और 10 हेक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई होगी। 10 परिवारों को इससे सीधे लाभ मिलेगा।

380 क्विंटल मछली उत्पादन होगा

मछली उत्पादन के मकसद से 19 तालाबों का निर्माण कराया गया है। जो पहले बन गये थे उनमें मछली का बीज डाला गया है लेकिन अगले साल से इन 19 तालाबों से 380 क्विंटल मछली उत्पादन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। समूह से जुड़ी महिलाओं का कहना है कि आमदनी होगी तो परिवार की आर्थिक स्थिति भी सुधरेगी और इसके सहारे आगे और व्यवसाय किया जा सकता है। जिले में 101 अमृत सरोवरों में सिंघाड़े की खेती की जायेगी। 240 क्विंटल

एक एकड़ में बाजरा की एसबीआई विधि से बुवाई करने पर मिल रही 3.5 क्विंटल अधिक उपज

मुरैना। एक हेक्टेयर क्षेत्र में बाजरा की एसबीआई विधि (सिस्टम ऑफ बाजरा इन्टेन्सीफिकेशन) यानि बाजरा की सघन पद्धति से बुवाई करने पर 350 किलोग्राम अधिक बाजरा की उपज प्राप्त की है, जिसकी कीमत 3 हजार 920 रूपए है। पोरसा विकासखण्ड के ग्राम करसण्डा गांव के किसान सुनील कुमार ने बताया कि मेरा पूरा परिवार मुख्यत: खेती पर निर्भर है। खरीफ सीजन में बाजरा हमारे क्षेत्र की मुख्य फसल है, क्योंकि इससे पशुओं के लिये चारे एवं दाने की उपलब्धता की पूर्ति आसानी से हो जाती है। अभी तक हम बाजरे की फसल परम्परागत पद्धति से ही करते थे।

श्री सुनील कुमार ने बताया कि पिछले दिनों मेरे खेत में पर एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेन्ट एजेन्सी (आत्मा) के अधिकारियों ने खेत पाठशाला का संचालन किया, इसके लिये मेरे खेत में एक हेक्टेयर क्षेत्र की अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन का आयोजन किया गया, इसमें एक एकड़ में बाजरा की बोवनी एसबीआई विधि सिस्टम ऑफ बाजरा इन्टेन्शीलफिकेशन (बाजरा की सघन पद्धति) से कराई गई। इस बोनी से 15 दिन के पूर्व नर्सरी तैयार कर पौधरोपण किया गया। साथ ही हमारे दूसरे खेत पर एक एकड़ में हमने परम्परागत तरीके से बोनी की जिसको कंट्रॉल प्लान्ट का नाम दिया। इस फसल के दौरान आत्मा एवं कृषि विभाग के अधिकारियों ने लोगों को उन्नत खेती के विस्तार पर भी प्रशिक्षण दिया।

किसान सुनील कुमार ने बताया कि फसल के पकने पर आत्मा एवं कृषि विभाग के अधिकारियों द्वारा अपने समक्ष दोंनो प्लांटों में से दो से तीन जगह से एक गुणा एक मीटर के प्लांट का चयन कर वहां से फसल कटाई एवं गहराई कर उपज ली।

इसमें कंट्रॉल प्लांट परम्परागत खेती से 1020 किलोग्राम बाजरा उत्पादन हुआ और एसबीआई की बोई गई फसल से 1370 किलोग्राम यानी परम्परागत बाजरा की फसल से 350 अधिक किलोग्राम बाजरा फसल का उत्पादन हुआ है।

किसान सुनील कुमार ने बताया कि एसबीआई पद्धति की फसल में नर्सरी लगाकर क्रमवार कुछ दूरी पर पौध लगाई जाती है, इससे पौध से कई शाखायें बड़ी मात्रा में फूड़ती है, उसे उत्पादन बढ़ता है। दाना भी अच्छा और अधिक मात्रा में होता है। किसान सुनील कुमार ने बताया कि इस एसबीआई बाजरा बुआई पद्धति से मुझे एक एकड़ में मात्र 3920 रूपए अतिरिक्त लाभ हुआ है। मैं अन्य किसान भाईयों से अनुरोध करूंगा कि वे भी बाजरा की एसबीआईबाजरा सघन पद्धति का अपनाकर दोगुना अधिक बाजरा का उत्पादन प्राप्त करें।

कलेक्टर ने बिसेंठा गांव में चौपाल लगाकर सुनी लोगों की समस्याएं

मुरैना। कलेक्टर अंकित अस्थाना ने मुरैना जनपद की ग्राम पंचायत बमरौली के ग्राम बिसेंठा में ग्रामीणों की समस्यायें सुनी और उनका मौके पर ही समाधान किया। इस अवसर पर जिला पंचायत के सीईओ डॉ. इच्छित गढ़पाले, एसडीएम मुरैना एलके पाण्डेय, जनपद सीईओ आरके गोस्वामी सहित बड़ी संख्या में ग्रामीणजन मौजूद थे।

कलेक्टर अंकित अस्थाना ने कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित बिसेंठा में बैठकर ग्रामीणों से संचालित योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी ली। कलेक्टर ने कहा कि पंचायत भवन प्रतिदिन खुलता है, स्कूल चलता है, सबंल योजना की सहायता मिलती है, पीडीएस वितरण होता है, स्कूल, आंगनवाड़ी में मध्यान्ह भोजन वितरित होता है, गर्भवती महिलाओं के प्रसव के लिये कहां ले जाना पड़ता है। यह समस्त चर्चायें ग्रामीणों के बीच बैठकर रूबरू होकर की। ग्रामीणों ने बताया कि 204 लोगों के कार्ड बने है, उन्हें राशन दिसम्बर माह का मिल चुका है।

ग्रामीणों ने बताया कि गांव में स्कूल के लिये भवन नहीं है, बच्चे एक खंडर के पास बैठकर पढ़ते है। शिक्षक नियमित आते है, गांव में सभी बच्चों को मध्यान्ह, भोजन मिलता है, सभी लोगों को खाद्यान्न मिलता है, किन्तु पटवारी गांव में नहीं आती हैं। इस पर कलेक्टर ने तत्काल व्यवस्थायें करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये।

कलेक्टर की पहल पर बिसेंठा में मिला स्कूल के लिये भवन - ग्राम बिसेंठा

के निवासियों ने कलेक्टर से कहा कि गांव के पास कृषि साख सहकारी समिति मर्यादित बिसेंठा का नवीन भवन बनकर तैयार हो गया है। जिसमें पीडीएस का वितरण, खाद आदि का वितरण होता है। पुराना भवन खाली है, कलेक्टर ने तत्काल प्राथमिक विद्यालय बमरौली को उस भवन में लगाने के निर्देश दिये।

ग्राम बिसेंठा में तत्काल होगा पटवारी पदस्थ

ग्राम बिसेंठा के निवासियों ने बताया कि गांव के 7 लोगों के नामान्तरण लंबित है, पटवारी आती नहीं है। वे गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं। कलेक्टर ने तत्काल एसडीएम श्री एलके पाण्डेय को आज ही नवीन पटवारी बिसेंठा में पदस्थ करने के निर्देश दिये, ताकि अगले दिन से पटवारी उपस्थित होकर नामान्तरण, बटवारा शेष प्रकरणों का निराकरण करें। कलेक्टर ने ग्रामीणों की मांग पर राजेश की पात्रता पर्ची एवं संबल की कार्ड बनाने की बात कही। उन्होंने कहा कि जो लोग शासकीय सेवक है या इनकम टेक्स जमा करते है या 5 हेक्टेयर से अधिक भूमि के कास्तगार है, उनको छोड़कर संबल कार्ड बनवाये जायें। कलेक्टर ने कहा कि मजदूरी सभी मिलती है, बिसेंठा गांव की आवादी 1100 लोगों की है। संबल मात्र 5 लोग है, इसके लिये जनपद सीईओ गांव में कैम्प लगाये। कलेक्टर ने मतदाता सूची में सभी के नाम जुड़वाने की बात कही।

ग्राम बिसेंठा में एनआरएलएम के माध्यम से बैंक सखी खोलने का निर्णय

ग्रामीणों ने बताया कि इस गांव के 45 लोगों को वृद्धावस्था पेंशन का लाभ मिलता है, किन्तु पैसे निकालने के लिये नूरावाद, मुरैना एवं रिठौराकलां तक जाना पड़ता है। कलेक्टर ने तत्काल जनपद सीईओ मुरैना को निर्देश दिये कि एनआरएलएम के सहयोग से आसपास के स्व-सहायता समूह से बैंक सखी खोली जाये, पेंशन आने के बाद तीन दिन ग्राम बिसेंठा में बैठकर पेंशन का वितरण करायें। शेष पात्र लोगों की पेंशन बनवाने के लिये पंचायत समन्वयक कैम्प लगायें।

भोपाल से तैयार होकर गए जूट के लैपटाप बैग, मंडला की कोदो-कुटकी से तैयार की गई कूकीज, पन्ना में बनीं आंवला की कैंडी भी

प्रवासी भारतीयों को रिटर्न गिफ्ट में दी जाएगी मप्र के जिलों की पहचान

जागत गांव हमार, भोपाल।

चार हजार प्रवासियों के इंदौर दौरे के बाद उनके जहन में मध्यप्रदेश की छाप छोड़ने के लिए शहर जहां सज-धजकर तैयार है, वहीं इन यादों को लम्बे समय तक संजोने के लिए मध्यप्रदेश के जिलों की पहचान रिटर्न गिफ्ट में दी जाएगी। भोपाल से तैयार होकर गए जूट के लैपटाप बैग में लगभग सभी जिलों के उत्पाद हैं।

शहर सज-धजकर प्रवासियों के स्वागत के लिए तैयार- इंदौर जिला प्रशासन, नगर निगम, आईडीए की दिन-रात की मेहनत रंग लाई है। शहर सज-धजकर प्रवासियों के स्वागत के लिए तैयार है। लगभग चार हजार प्रवासियों के दौरे को लेकर तैयारियां हो चुकी हैं, वहीं अब उनके रिटर्न गिफ्ट को लेकर पैकिंग शुरू हो गई है। प्रवासी मध्यप्रदेश के दौरे के बाद जहन में जहां यहां की स्वच्छता और मेहमाननवाजी लेकर जाएंगे, वहीं उनके हाथों में रिटर्न गिफ्ट के रूप में जो बैग दिया जाएगा, उसमें पूरे मध्यप्रदेश के उत्कृष्ट उत्पाद शामिल किये जा रहे हैं।

ठंड के दिनों में मंडला जिले में आदिवासियों को पोषण देने वाली कोदो कुटकी से प्रवासियों के लिए कुकीज तैयार की गई है, वहीं मध्यप्रदेश का फेमस गुड़ की पोटली भी बैग में समाहित की गई है। पन्ना में बनी आंवला केंडी का बाक्स भी रखा जा रहा है।

मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में तैयार किए जा रहे उत्पाद को प्रमुखता

विदेशों से अपने देश लौट रहे प्रवासियों के लिए जहां विभिन्न तरह के सांस्कृतिक आयोजन की तैयारी की जा रही है, जिससे अपने देश की संस्कृति की छवि उनके दिमाग में छाप छोड़े, वहीं मध्यप्रदेश के विभिन्न जिलों में तैयार किए जा रहे उत्पाद को प्रमुखता दी जा रही है, जिसमें भोपाल में बने जूट बैग, देवास में बने बेम्बू बाक्स और ईको फ्रेंडली तरीके से बनाई गई बेम्बू शिल्क का ट्रोल, बाग प्रिंट किया हुआ ट्रोल, कोदोकुटकी से बनी कुकीज, पन्ना की आंवला केंडी, मध्यप्रदेश का गुड़ और गौंड आटज से तैयार किया गया मुमेन्टो, वहीं ट्रायवल आर्ट से तैयार की गई छोटी थैलियां दी जाएंगी। ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में ये सभी सामान, भोपाल से तैयार होकर आए जूट बैग में रखा जा रहा है।

केले के पत्तों से बने कागज भी

आने वाले मेहमानों को मध्यप्रदेश के उत्पादों से रूबरू कराने के लिए विशेष पेम्पलेट तैयार किये गये हैं। ये पेम्पलेट जिन ए-4 साइज के पेपरों पर प्रिंट किए गए हैं, ये पेपर बुरहानपुर के केले के पेड़ों से तैयार किए गए हैं। बुरहानपुर से विशेष तौर पर किए गए इन ए-4 साइज के पेपर को इस रिटनर्ज गिफ्ट में समाहित किया जा रहा है, वहीं मध्यप्रदेश की महिलाओं द्वारा हाथों से तैयार की गई डायरी, जहां भारतीय झंडे की प्रतिकृति प्रवासियों के साथ जाएगी, वहीं एक इम्पोर्टेड पेन भी इस बाक्स में शामिल है।

डॉ. मांडविया ने 9000 से अधिक किसानों और खुदरा विक्रेताओं से की बात

पीएम किसान समृद्धि केन्द्र में बदलेंगी 2.5 लाख से अधिक फर्टिलाइजर दुकानें

जागत गांव हमार, नई दिल्ली।

भारत सरकार किसानों के हित में क्रांतिकारी कदम उठा रही है। ऐसे ही एक महत्वपूर्ण कदम के रुप में, उर्वरक खुदरा दुकानों को प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केन्द्रों (पीएमकेएसके) में परिवर्तित किया जा रहा है। ये पीएमकेएसके कृषि संबंधी सभी कार्यों के लिए एक नोडल बिंदु के रूप में कार्य करेंगे और नवीनतम नवाचारों, सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों, ज्ञान, तकनीकों और परीक्षणों का प्रसार करेंगे जो किसानों को न केवल उनकी उत्पादकता बढ़ाने बल्कि उत्पादन की लागत को कम करने में मदद करेंगे। यह बात केन्द्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ. मनसुख मांडविया ने देश भर के लगभग 9000 पीएमकेएसके के एकत्र किसानों को वर्चुअली संबोधित करते हुए कही। उन्होंने छह राज्यों रामनगर (उत्तर प्रदेश), कोटा (राजस्थान), देवास (मध्य प्रदेश), वडोदरा (गुजरात) के पीएमकेएसके के किसानों और खुदरा विक्रेताओं और एलुरु (आंध्र प्रदेश) और राजापुरा (पंजाब) के खुदरा विक्रेताओं के साथ भी बातचीत की।

डॉ. मांडविया ने कहा देश में लगभग 2,62,559 सक्रिय खुदरा दुकानों को चरणबद्ध तरीके से पीएमकेएसके में परिवर्तित किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 'रूपांतरण की यह प्रक्रिया सुनिश्चित करेगी कि पीएमकेएसके में प्रदान किए जाने वाले उत्पादों और सुविधाओं की विस्तृत श्रृंखला देश के सभी किसानों तक पहुंचे। पीएमकेएसके भविष्य में किसानों के लिए एक प्रमुख मंच साबित होगा जो किसानों की रोजमर्रा की समस्याओं से निपटने में मदद करेगा और कम से कम समय में उनकी चिंताओं को दूर करेगा।'

इस अवसर पर, डॉ. मांडविया ने कहा कि भारत सरकार किसानों को समर्थ बनाने के लिए हर संभव उपाय करने के लिए समर्पित है। चाहे वह पीएम किसान सम्मान निधि जैसे कार्यक्रमों के माध्यम से वित्तीय सहायता हो, या नैनो यूरिया और वैकल्पिक उर्वरकों के नए वैज्ञानिक नवाचार, व्यापक कदम उठाए जा रहे हैं। खेती में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले उर्वरकों की उपलब्धता सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता रही है और वैश्विक उथल-पुथल के बावजूद, सरकार अत्यधिक रियायती दरों पर उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कर रही है।

पीएमकेएसके खोलना एक बड़ा कदम

पीएमकेएसके के महत्व पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि 'पीएमकेएसके खोलना एक बड़ा कदम है, जो किसानों की विभिन्न प्रकार की जरूरतों को पूरा करने में मदद करेगा जैसे कृषि संबंधी जानकारी (उर्वरक, बीज और कीटनाशक) प्रदान करना और मिट्टी, बीज और उर्वरकों के लिए परीक्षण सुविधाएं प्रदान करना। कार्यक्रम के दौरान अरुण सिंघल, सचिव, उर्वरक विभाग, नीरजा आदिदम, अपर सचिव सहित मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

मुर्गियों के लिए भोपाल में विकसित टीका एच9एन2 की तकनीक का हस्तांतरण

भोपाल। आईसीएआर-एनआईएचएसएडी, भोपाल के वैज्ञानिकों द्वारा विकसित 'मुर्गियों के लिए निष्क्रिय कम रोगजनक एवियन इन्फ्लुएंजा (एच9एन2) टीके' को मेसर्स ग्लोबियन इंडिया प्रा. लि., सिकंदराबाद, मेसर्स वेंकटेश्वर हैचरीज प्रा. लि., पुणे, मेसर्स इंडोवैक्स प्रा. लि., गुडगाांव और मेसर्स हेस्टर बायोसाइंसेज लि., अहमदाबाद को हस्तांतरित कर दिया गया। यह सुविधा एनएएससी, नई दिल्ली में एग्रीनोवेट इंडिया लि. (एजीआईएन) द्वारा प्रदान की गई।

इस कार्यक्रम में डॉ. हिमांशु पाठक, सचिव (डीएआरई) तथा महानिदेशक (आईसीएआर) एवं अध्यक्ष, एजीआईएन, डॉ. बी.एन. त्रिपाठी, डीडीजी (पशु विज्ञान), डॉ. प्रवीण मलिक, सीईओ, एग्रीनोवेट इंडिया लि., डॉ. अनिकेत सान्याल, निदेशक आईसीएआर-एनआईएचएसएडी, वाणिज्यिक फर्मों के प्रतिनिधि, आईसीएआर और एजीआईएन के अन्य अधिकारी शामिल हुए। डॉ. हिमांशु पाठक ने एच9एन2 वायरस के लिए पहले स्वदेशी टीके के विकास में आईसीएआर-एनआईएचएसएडी के वैज्ञानिकों के गंभीर प्रयासों की सराहना की और उद्योग जगत को इसके प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण संबंधी प्रयासों के लिए एग्रीनोवेट इंडिया लि. (एजीआईएन) की सराहना की। डीडीजी (एएस) ने जोर देकर कहा कि यह टीका भारत और विदेश दोनों ही बाजारों के मानकों पर खरा उतरेगा। यह टीका बीमारी से होने वाले आर्थिक नुकसान को कम करके मुर्गीपालन में संलग्न किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जय माता प्रिंटर्स, मं.नं.1, पेमदीपुरा बापू कालोनी के पास चिकलोद रोड, जहांगीराबाद, भोपाल(मप्र) से मुद्रित एवं 97 विवेकानंद कालोनी, मुरैना मप्र से प्रकाशित।
संपादक: **अवधेश डंडोतिया***, 9425128418, स्थानीय संपादक: **शिवप्रताप सिंह जादौन,** 8085193661 ईमेल-jagatgaon.bpl@gmail.com, (सभी विवादों का न्याय क्षेत्र भोपाल होगा)। संपर्क भोपाल कार्यालय-संपर्क 9229497393, 9425048589